



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2018/चैत्र 14, 1940

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2018/CHAITRA 14, 1940

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

**जांच शुरुआत अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2018

(मध्यावधि समीक्षा जाँच)

**मामला सं. (एमटीआर) 2/2018**

**विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी व्यासों के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच (एमटीआर) की शुरुआत ।**

**सं. 7/13/2018-डीजीएडी.— 1.** यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 14/02/2013-डीजीएडी के द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी व्यासों वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 04/2015 दिनांक 13 फरवरी, 2015 के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

**क. मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने के लिए अनुरोध**

2. संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं की एक एसोसिएशन अलाय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएफपीए) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है जिससे ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।

**ख. समीक्षा के लिए आधार**

3. मै. एचईजी लि. और मै. ग्रेफाइट इंडिया लि. (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से घरेलू उद्योग कहा गया है) द्वारा दायर आवेदन के आधार पर दिनांक 20 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 14/02/2013-डीजीएडी द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जाँच शुरू की गई थी।
4. आवेदक ने अनुरोध किया है कि :
  - i. आय, लाभ और नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) के अनुसार घरेलू उद्योग के आर्थिक कार्यनिष्पादन में काफी सुधार हुआ है।
  - ii. चीन जन. गण. भारत को संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख निर्यातक देश था। तथापि, हाल के वर्षों में चीन जन.गण. की सरकार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले अनेक औद्योगिकी संयंत्रों को बंद कर दिया है।
  - iii. घरेलू उद्योग पिछले कुछ वर्षों में संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का निर्यात कर रहा है और भारतीय बाजार में मांग की उपेक्षा कर रहा है।
  - iv. यह कि घरेलू उद्योग को अब कोई क्षति नहीं हो रही है और परिणामस्वरूप वर्तमान शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत हुई है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

5. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. से "सभी व्यासों वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स" हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का मुख्य प्रयोग फर्नेसों में फेड चार्ज में इलेक्ट्रिक करेंट को भेजकर इस्पात को गलाना है। इस्पात निर्माण की इस पद्धति को सेकेंडरी इस्पात निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को करेंट केरिंग कंडक्टर्स के रूप में आर्क फर्नेसों में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें काफी उच्च दर पर विद्युत फीड की आवश्यकता होती है।

ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को मोटे तौर पर अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) और अन्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनमें उच्च पावर ग्रेड (एचपीजी) और सामान्य पावर ग्रेड (एनपीजी) शामिल हैं। तदनुसार, उनमें ऐसे उच्च करेंट और विद्युत फीड लेने के लिए सक्षम होने की विशेषताएं होनी चाहिए।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 8545 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है और उसे प्राथमिक रूप से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद संख्या 85451100 और 85451900 के अधीन आयात किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तु एक समान हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित पीयूसी और संबद्ध देश से आयातित पीयूसी में भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के अनुसार तुलनीय विशेषताएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अंतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

#### **घ. शामिल देश**

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

#### **ड. जाँच की शुरुआत**

9. 1 मार्च, 2011 को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 द्वारा यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 का उप नियम (1) और (1क) जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार पठित है:

*'(1) अधिनियम की धारा 9क के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन की प्रतिपूर्ति करने की समयावधि तक और उसकी आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।*

*(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है के अनुरोध पर और जब निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने से एक तर्कसंगत अवधि बीत गई हो, किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से तब उसे हटाने की सिफारिश करेंगे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है।*

10. पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, प्राधिकारी के लिए समय-समय पर स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है के अनुरोध पर किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।
11. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उचित मानते हैं।

#### **च. प्रक्रिया**

12. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना जो लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बनाने के लिए परिवर्तित परिस्थितियां दर्शाती है, को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 14/02/2013-डीजीएडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 04/2015 द्वारा लगाये गये निश्चयात्मक शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उचित है और प्राधिकारी एतद् द्वारा संबंधित नियमावली के नियम 23 के साथ सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के उपबंधों के अनुसार जांच की शुरुआत करते हैं ताकि पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके। इस समीक्षा में दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 14/02/2013-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

#### **छ. जांच अवधि**

13. वर्तमान जांच के प्रस्तावित जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2014 - मार्च 2015, अप्रैल 2015 - मार्च 2016, अप्रैल 2016 - मार्च 2017 और जांच की अवधि शामिल होगी।

#### **च. सूचना प्रस्तुत करना**

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-
15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना अनुरोध निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
भारत सरकार  
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग 5 संसद मार्ग,  
नई दिल्ली- 110001**

16. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**झ. समय-सीमा**

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी संबंधित नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना हार्ड कॉपियों और साफ्ट कॉपियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

19. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
- (क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
- (ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
20. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पांच-पांच (5-5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
21. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का

दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
25. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### ठ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**New Delhi, the 4<sup>th</sup> April, 2018**(Mid Term Review Investigation)****Case No. (MTR)2/2018**

**Subject : Initiation of Mid-term Review (MTR) investigation with regard to the anti-dumping duties in force on the imports of Graphite Electrodes of all diameters originating in or exported from China PR.**

**No. 7/13/2018-DGAD.**—1. Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), notified its final findings vide Notification No. 14/02/2013-DGAD dated 19<sup>th</sup> November 2014 and recommended imposition of definitive anti-dumping duty on import of “Graphite Electrodes of all diameters” (hereinafter referred to as “subject goods” or “the product under consideration”) originating in or exported from China PR and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 04/2015 dated 13<sup>th</sup> February 2015.

**A. REQUEST FOR INITIATION OF MID TERM REVIEW**

2. Alloy Steel Producers Association of India (“ASPA”) (hereinafter referred to as “the applicant”) an association of importers/users of the subject goods, has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing antidumping duties are no longer warranted.

**B. GROUNDS FOR REVIEW**

3. An anti-dumping investigation on imports of the subject goods was initiated vide Notification. No.14/02/2013- DGAD dated 20th May, 2013 on the basis of an application filed by M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd (hereinafter collectively referred as “Domestic Industry”).
4. The Applicant has submitted that:

- i. The economic performance of the domestic industry in terms of revenue, profits and return on capital employed (ROCE) has improved significantly.
- ii. China PR was one of the major exporting countries of the subject goods to India. However, in the recent years, the Government of China PR has shut down many industrial plants producing the subject goods on account of environmental concerns.
- iii. The Domestic Industry has been exporting significant volumes of the subject goods in the last few years and is neglecting the demands of the Indian market.
- iv. That the domestic industry is not suffering injury any longer and as a consequence, a need for reviewing the current duties has arisen.

### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Graphite Electrodes of all diameters” from China PR. The main function of Graphite Electrodes is to be used for melting of steel by passing electric current into the charge fed into the furnaces. This method of steel making is also known as secondary steel making. Graphite Electrodes are used in arc furnaces as current carrying conductors and are required to carry a very high rate of power feed. Graphite electrodes can be broadly categorized as Ultra High Power (UHP) and others which include the High Power Grade (HPG) and Normal Power Grade (NPG). Accordingly, they are required to have properties capable for taking such high current and power feeds.
6. The product under consideration is classified under Customs Tariff Heading 8545 and are primarily imported under tariff item number 85451100 and 85451900 of the Custom Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
7. The applicants have claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being imported into India. The applicants have claimed that PUC produced by the applicants and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

### **D. COUNTRY INVOLVED**

8. The country involved in the present investigation is China PR.

### **E. INITIATION**

9. Sub Rule (1) and (1A) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011, inter alia, reads as follows:
  - (1) *Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.*
  - (1A) *The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping*



*duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that injury to the domestic industry is not likely to recur, if the said antidumping duty is removed or varied and therefore no longer warranted.*

10. In terms of aforesaid rules, the Authority shall review from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.
11. On the basis of information made available by the aforementioned Applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

#### **F. PROCEDURE:**

12. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No. 14/02/2013-DGAD dated 19<sup>th</sup> November 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 04/2015 dated 13<sup>th</sup> February 2015 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties. The review will cover all aspects of Notification No.14/02/2013-DGAD dated 19<sup>th</sup> November 2014.

#### **G. PERIOD OF INVESTIGATION**

13. The period of investigation (POI) for the present investigation is from April, 2017 to March, 2018. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2014-March 2015, April 2015-March 2016, April 2016-March 2017 and the POI.

#### **H. SUBMISSION OF INFORMATION**

14. The known exporters in the subject country and its Government through its Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,  
New Delhi-110001**

16. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**I. TIME LIMIT**

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

**J. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

19. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
20. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.
21. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to

make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
25. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**K. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

26. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**L. NON-COOPERATION**

27. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority